



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12331

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 12485 वर्ष 2025

धर्मपाल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : कृष्ण प्रताप यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई। आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री कृष्ण प्रताप यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राम मोहित यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 231 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 317(2), 309(6), 61(2) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25 के अंतर्गत, थाना - धनारी, जिला - संभल में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त पुरुषोत्तम को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 39136 वर्ष 2025 में दिनांक 15.11.2025 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास की व्याख्या की जा चुकी है। वह दिनांक 01.09.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
6. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा परस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रकाश में, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

8. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक - धर्मपाल को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 19 जनवरी, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"